राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 30 अंक : 5

सितम्बर - अक्तूबर 2007

Karnataka Governor Sri Rameshwar Thakur addressing delegates of the National Seminar on "National Knowledge Commission's Recommendation on Higher Education" conducted at Bangalore on 19th & 20th September 2007.

Inaugural function of the National Seminar on "NAAC Accreditation Methodology: Assessment & Suggestions" conducted at Pune on 25th August 2007

भोपाल में अभाविप प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन करते आरएसएस सह सरकार्यवाह मा.सुरेश सोनी

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 30 अंक : 5, ● सितम्बर–अक्तूबर 2007

संरक्षक
अतुल कोठारी

संपादक
डा. मुकेश अग्रवाल

प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा

संपादक मंडल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

फोन : 011 – 23093238 , 27662477
E-mail : chhatrashakti@yahoo.co.in
Website : www.abvp.org

मूल्य : एक प्रति रुपए 10/–

छात्रशक्ति

"राष्ट्रीय छात्रशक्ति" की ओर से सभी पाठकों एवं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ।

विषय सूची

कविता : 4

प्रमुख लेख

विश्व धरोहर है श्री रामसेत....6

The Ram Sethu is our heritage....7

भारत का युवा मन आत्मगौरव की खोज में....9

राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष तेज करने की जरूरत..11

Rama Sethu a man-made structure....13

रामसेतु आंदोलन और राष्ट्रीय मीडिया....18

मुलाकात

अभाविप पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सुश्री गीता ताई गुंडे....24

यौन शिक्षा : विरोध के प्रखर स्वर 20

परिचर्चा

धर्म के आधार पर आरक्षण : उचित या अनुचित?....16

Report

National Seminar on Knowledge Commission....22

National Seminar on NAAC....26

परिषद् गतिविधियां....27

आह्वान

* क्या आप देश की वर्तमान दशा पर चिन्तित हैं?
* क्या आपको दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में छात्र–युवा ही सक्षम हैं?

यदि हां

* तो अपने क्षोभ को शब्द दीजिए और विश्वास कीजिए,आपमें क्षमता है कलम की नोंक से दुनिया का रुख बदलने की।
* अपने विचारों को साहित्य की किसी भी विधा में शब्द दें तथा राष्ट्रीय छात्रशक्ति द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,136,नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली–110001 को प्रेषित करें।

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक, एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा।

फेंक जहां तक भाला जाए

– वाहिद अली वाहिद –

कब तक बोझ संभाला जाए,
युद्ध कहां तक टाला जाए।

दूध छीन बच्चों के मुख से,
क्यों नागों को पाला जाए।

दोनों और लिखा हो भारत,
सिक्का वहीं उछाला जाए।

तू राणा का वंशज है तो,
फेंक जहां तक भाला जाए।

इक बिगड़ैल पड़ोसी को,
फिर श्शीशे में ढाला जाए।

'वाहिद' के घर दीप जले तो,
मंदिर तक उजीयाला जाए।

सरकारी देवालय

– सीआर कासवान –

'न्याय कमजोर को चाहिए
न्याय शक्तिशाली दे सकता है,
शक्तिशाली या तो व्यक्ति या व्यवस्था।

जब व्यक्ति शक्तिशाली तो राजतंत्र,
व्यवस्था शक्तिशाली तो प्रजातंत्र।'

'राजतंत्र में आदेश, प्रजातंत्र में प्रक्रिया
राजतंत्र के आदेश में दोषी को कम या ज्यादा
सजा मिलने की संभावना बनी रहती है,
प्रजातंत्र की प्रक्रिया में दोषी के बच नीकलने की
संभावना बनी रहती है।

समानता है कि कमजोर को दोनों में
सजा मिलने की संभावना बनी रहती है।'

क्यों नहीं कुछ हुआ

– आशीष कुमार 'अंशु'–

मन्दिर गिरा
हल्ला हुआ,
मस्जिद गिरी
दंगा हुआ।

क्यों नहीं कुछ हुआ
जब गिर गया इंसान,
जब गिर गया उसका जमीर
जब गिर गया उसका ईमान।

क्या गम है

माताए लौहो कलम छीन गई तो क्या गम है
कि खूने दिल में डूबे ली हैं उंगलियां मैने,
जुबां पे मुहर लगी है तो क्या कि रख दी है
हरेक हलकाए जंजीर में जुबां मैने।

व्यंग्य

मैने उनपर व्यंग्य लिखा
वही उनका विज्ञापन निकला,
वही मेरी सबसे कमाऊ रचना निकली
वही हिन्दी साहित्य के इतिहास में समाहृत भी हुआ।

सोचना

अपने बारे में सोचना
उन्हें हमेशा दुनियां के बारे में सोचने जैसा लगता था,
और इस तरह दुनियां के बारे में सोचना
उन्हें हमेशा अच्छा लगता था।

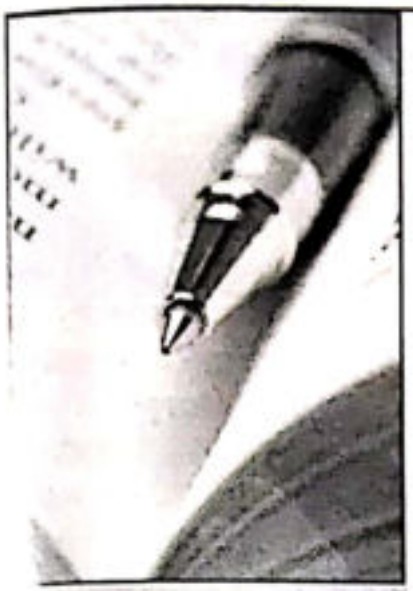

संपादकीय

संप्रग सरकार का अक्षम्य अपराध

देश की राजनीति किस कदर प्रदूषित हो गई है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रामसेतु मुद्दे पर यूपीए सरकार के पुरातत्व विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। हद तो तब हो गई जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने सरेआम कहा, 'क्या राम ने इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययन किया था? वह एक शराबी था। राम के होने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है।' ऐसा करके यूपीए सरकार और करुणानिधि ने अक्षम्य अपराध किया है। करोड़ों हिन्दुओं का अपमान किया है। सरकार के बयान से पूरे देश में भूचाल आ गया है। देश भर में लोग मनमोहन सरकार और करुणानिधि के विरोध में सड़कों पर उतर आए है। विश्व हिन्दू परिषद् ने देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया, जिसमें देशवासियों ने बढ चढकर हिस्सा लिया। यह आंदोलन ऐतिहासिक रूप से सफल रहा, जिसके दबाव में यूपीए सरकार को यह राष्ट्रविरोधी हलफनामा वापस लेना पड़ा।

रामसेतु देश के करोड़ों हिन्दुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। दरअसल, कम्युनिस्टों की बैशाखी पर टिकी कांग्रेस–नीत केन्द्र सरकार सुनियोजित तरीके से भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। सेतु समुद्रम परियोजना तो सिर्फ बहाना है। भला कौन नहीं चाहेगा कि देश का विकास हो? सेतु समुद्रम परियोजना का विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध तो एलाइनमेंट को लेकर है। राम सेतु तोड़े बिना भी सेतु समुद्रम परियोजना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार किसी भी कीमत पर रामसेतु को तोड़ने पर आमादा है। सरकार के इस फैसले का व्यापक पैमाने पर विरोध हो रहा है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखा है कि 'सेतुसमुद्रम देश और स्वराज विरोधी कार्य है।' दूसरी ओर पर्यावरणविदों ने भी आपत्ति प्रकट की है कि राम सेतु को तोड़े जाने से समुद्र के भीतर भूस्खलन और भूकंप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। देश के छात्र–नौजवान यूपीए सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह जन भावनाओं का सम्मान करते हुए अविलंब सेतु समुद्रम परियोजना बंद करे अन्यथा यूपीए सरकार का सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा।

छात्र संघ चुनाव पर रोक अलोकतांत्रिक

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी है। ऐसा करके प्रदेश सरकार ने छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलने का प्रयास किया है। सुश्री मायावती के इस आदेश के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश सरकार के इस निर्णय का देश भर में विरोध हो रहा है। छात्र संघ चुनावों पर महज इस आधार पर प्रतिबंध लगा देना कि इससे पढाई का माहौल खराब होता है और विश्वविद्यालय परिसर में गुण्डागर्दी को बढावा मिलता है, सरासर अन्याय है। इस तर्क को माने तब तो ऐसा होना चाहिए कि जहां छात्र संघ चुनाव नहीं होते है वहां शैक्षणिक गतिविधियां उच्च स्तर की होनी चाहिए लेकिन हकीकत इसके उलट ही बयां करता है। वहीं जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय जहां प्रतिवर्श छात्र संघ चुनाव होते है वह देश के उत्कृश्ट विश्वविद्यालय है। दरअसल, बात कुछ और है। इतिहास इस बात का गवाह है कि दश की शासक पार्टियों को हमेशा छात्रशक्ति से चुनौती मिलती रही हैं क्योंकि छात्र स्वभावतः अनाचार के खिलाफ तनकर खड़े होते है। मायावती सरकार तत्काल छात्र संघ चुनाव बहाल करे अन्यथा छात्रशक्ति उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। ■

विश्व धरोहर है श्री रामसेतु

डा.मुरली मनोहर जोशी
पूर्व केन्द्रीय मंत्री

संप्रग सरकार द्वारा रामसेतु के मामले में जिस तरह का गोलमाल किया जा रहा है, यह स्थिति चिन्तनीय है। पहला तो यह कि सरकार ने आचार्यों, सुनामी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, विद्वानों तथा पूर्व–जस्टिस कृष्ण अय्यर व पूर्व–जरिटस, पदम भूषण के. टी. थामस जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उचित राय की उपेक्षा की। साथ ही, इसने रामसेतु को नष्ट होने से बचाने हेतु, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के एलाइनमेंट को बदलने के लिए समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रस्तुत 36 लाख हस्ताक्षरित आवेदन को कूड़ेदान में डाल दिया। यहां तक कि सरकार, उस वक्त भी इस मामले की गंभीरता समझने में नाकाम रही, जब राज्य सभा में बहस के दौरान महत्वपूर्ण नेताओं ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की थी। सरकार को दलों से ऊपर उठकर अनेक महत्वपूर्ण राजनेताओं के उन बयानों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें श्री राम को राष्ट्रीय महापुरुष ही नहीं, बल्कि ईश्वर का अवतार स्वीकार किया है।

दूसरा–जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठा, तो सरकार ने बड़ी निर्लज्जता से एक हलफनामा दायर किया, जिसमें श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। यह हलफनामा राष्ट्र और परंपराओं पर हमला है और वास्तव में यह स्वतंत्रता संग्राम का भी अपमान है, जिसका मकसद, महात्मा गांधी के अनुसार, रामराज्य की स्थापना करना था। सच तो यह है कि संप्रग सरकार लोगों की भावनाओं का जरा भी सम्मान नहीं करती। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जनता पुल को सेतु मंदिर, राम सेतु और आदमपुल, एडम ब्रिज, आदि सेतु के रूप में देखती है। तीसरा, ईशनिंदात्मक हलफनामे को पूरी तरह से वापस लेने व देश से माफी मांगने के बजाय, संप्रग सरकार यह जानने में भी असफल रही कि हलफनामें को किसने तैयार किया और किस स्तर पर इसे स्वीकृति मिली? वास्तव में सरकार को श्री राम के इस घोर अनादर की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सरकार को सभी 'ड्रेजिंग' कार्य तत्काल बंद कर देने चाहिए और उसे ऐसे उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे करोड़ों देशवासियों की आहत भावना शांत हो। दूसरी तरफ, सरकार पूरक हलफनामे दाखिल करने की कोशिश कर रही है। जहाजरानी मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर करना चाहता है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के भीतर अतिशय भ्रम, इस बात का संकेत देता है कि पार्टी के विभिन्न नेताओं के बीच आरोप–प्रत्यारोप का युद्ध जारी है। एक ऐसी सरकार जिसे अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, परंपरा, साहित्य और राम जैसे महापुरुषों के कृत्यों तथा वाल्मिक जैसे संतों, जिन्होंने सनातन काल से राष्ट्र के मूल्यों को पोषित किया, से पूर्णत अनभिज्ञ है और उसे अस्वीकार भी करती है, वह शासन में रहने के काबिल नहीं।

इस आन्दोलन के साथ समाज के हर वर्ग से लोग सामने आए और राम सेतु के तोडे जाने का दृढता से विरोध किया और मांग की कि इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाय। राम सेतु को विश्व धरोहर घोषित किया ही जाना चाहिए और उन सभी गतिविधियों को बंद किया जाना चाहिए, जिससे पुल नष्ट होता हो या होने की संभावना हो। साथ–साथ संप्रग सरकार द्वारा अपमानजनक हलफनामें का प्रारूप तैयार करने वालों की जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए।

उन वक्तव्यों की भी गंभीर निंदा होनी चाहिए, जिसमें प्रोजेक्ट के रिएलाइनमेंट को अराष्ट्रीय कहा गया है। उन विभाजनकारी कथनों/तर्कों की घोर आलोचना क्यों न की जाए, जो कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी व तर्क–वितर्क के जरिए देशवासियों को भौगोलिक, भाषाई और जातीय आधार पर बांटने की कोशिश करती है। इन सिद्धांतों को विद्वानों तथा जनता ने पूर्णतः नकार दिया है।

यदि संप्रग सरकार के घटक दल राम का अपमान जारी रखते हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार का समर्थन इन कथनों से है तथा वह इस राष्ट्रीय अपमान से आंखें मूंद रही है। ऐसे तत्वों को इस तरह के बयान जारी करने से बाज आना चाहिए, जो राष्ट्रीय ताने–बाने को कमजोर करता है। यही नहीं, इसका घातक असर देश की एकता और अखंडता पर भी पडेगा, जिसके लिए केंद्र की कांग्रेस–नीत सरकार अकेली जिम्मेदार होगी।

राम सेतु की रक्षा, सरंक्षण व राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सेतु समुद्रम को घोषित किए जाने का आंदोलन, रामेश्वरम् राम सेतु रक्षा मंच द्वारा चलाया जा रहा है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, जिसे पार्टियों से ऊपर उठकर जनता एवं धार्मिक मतावलंबियों का पूर्ण समर्थन हासिल है। ■

The Ram Sethu is our heritage
WE SHALL PROTECT IT

By Subramanian Swamy

The Dravidian Kazhagam, a British imperialist stooge organisation, has recently threatened to burn the myana in a public protest against ryan Supremacy" for opposing the struction of the Ram hu in the implementation he Sethusamudram Ca- Project.

The Dravida Movement which includes IK, MDMK, PMK, and DK parties, is a vement of atheists, which has turned its ire on agwan Sri Ram, the King of Ayodhya, and nts the Ram Sethu to be demolished because it a symbol of "North Indian" domination. This ows the bias and malice behind the determination to destruct the Ram Sethu. No self-respecting Hindu must permit this vandalism.

The demolition also would facilitate the anti-Indian terrorist LTTE's brigand boats to move quicker from Tuticorin to Chennai on the Palk ait, and on international waters. At present, the Ram Sethu stands in the way. Hence their vociferous support to Dravidian Movement parties for the Sethusamudram Ship Canal Project [SSCP].

To begin with, Sri Ram really emerged in national perception as a Maryada Purushottam divinity as distinct from a young dutiful prince of Ayodhya only after his sojourn to South India. Professor Suvira Jaiswal [www.thehindu.com/2007/03/12/stories] who has become the President of the Indian History Congress recently, in her S.C. Misra Memorial Lecture states that King Ram of Ayodhya was transformed into Bhagwan Sri Ram of the whole nation, i.e., as a re-incarnation of Vishnu because of the Tamil Vaishnava saints, Alwars, who sang praises of the qualities of Sri Ram. She also states that Chola and Pandya Kings despite being Shaivites, built the first temples for Sri Ram as a deity. Thus, while Raja Ram may be regarded as a 'northerner' from Ayodhya, nevertheless Bhagwan Sri Ram as a divine incarnation is the revelation of Tamil saints incorporated into the Hindu religion nationally. Sri Ram is in fact a symbol of our nation's oneness. Alwars and Nayanmar saints also propagated what the Dravidian Movement needs to learn fast: God is universally accessible, and grants salvation irrespective of caste to all those who worship him with complete devotion. God is not pro-any caste or where one is born. If such is the faith, who is the government to question it? As the Punjab & Haryana High Court division bench opined in 1993 in the Brahmasaravor case, even a stone is an ancient national monument if the people have faith in it.

While the Hindu scriptures have given vivid and moving description of the construction of the Ram Sethu, its existence has now been confirmed by two scientific sources. In the first, the present configuration of the Ram Sethu has been photographed by US National Aeronautics and Space Agency [NASA] by their satellites, and colour photos of the same are widely available on the NASA website. These photos establish the Sethu's existence as a chain of shoal stones.

The Department of Earth Science of the Government of India in a report to the President of India has stated that shoal stones placement make out that they were "deliberately placed there". That is, as if it was constructed in the manner described by the Valmiki, Kamban, and Tulsidas, saints who authored the Ramyana epic at different points in time in Sanskrit, Tamil and Hindi. NASA also establishes the age of the shoal stones as 1,750,000 years ago. The bridge formation itself by placing these stones one by one, according to the Earth Science Department, is not less than 9000 years.

Such independent corroboration therefore cannot be dismissed as mere coincidence and not worthy of notice as the DMK nominee in the union ministry of shipping T.R. Baalu has been saying. At the very minimum it requires a full inquiry as to whether or not the said Ram Sethu is a Hindu heritage site. Millions believe it to be so, and hence the government cannot take a narrow cynical view of such faith.

The objective of the Rs. 2427 crore SSCP nevertheless could be a worthy one, and for the national good if the calculations and data used are accurate. But a closer look using the analysis of Dr. Jacob John [published in Economic and Political Weekly, July 21, 2007], suggests that the entire economic cost-benefit analysis made by the Union Shipping Ministry and presented in a Detailed Project Report [DPR] to the Union Cabinet for approval of the project is bogus and aimed at misleading the nation about the financial viability of the project.

That is, while no rational opinion is against the project per se if it is viable, what is however sought is a feasible amendment of the SSCP, to avoid vandalizing the Ram Sethu by destructing it, and thereby hurting the religious sentiment of millions of Hindus.

The objective of SSCP can be achieved by digging through the 15 kilometre mainland stretch between Pamban and Dhanushkodi, adjacent to the Ram Sethu thereby leaving hoary Sethu intact. This accommodative approach of seeking of an alternative was followed by the Delhi Metro when its underground route digging came too close to the Qutub Minar. This will not only be welcome but the dredging costs on land will be much lower.

Moreover, retention of the Ram Sethu as it is, will ensure as it did in the past the minimisation of the damage from the tsunami disaster when the spread of the massive displacement of sea water caused by plate tectonic earthquake in Aceh reached the shores of India. The Ram Sethu acted as a wave and speed-breaker, thus saving enormous number of lives and damage to property.

I would therefore suggest that the SSCP be put on hold, and the alternative canal route be researched by a committee of experts and an amended project report be prepared. This is incidentally the opinion of a very wise Sub-Judge Mohammed Asif of the Ramnathapuram Subordinate Court. On February 23, 2007 while ruling on a petition challenging the SSCP he stated: "Imperatives of development and our commitment to protect heritage are two ends. A careful, intelligent balance should be struck between the two. Final opinion could be pronounced on issues raised by the petitioners only after subjecting their documents to thorough scrutiny with opinion of experts in the field."

The Ram Sethu is a living miracle, and therefore the Government of India ought to approach UNESCO to get it declared as the 28th World Heritage Site. The Tourism Ministry should also develop the area to vest it with the essential infrastructure so that pilgrims can come from far and wide.

[Courtesy: Organiser]

[Author is former Union Commerce and Law Minister and President of Janatha Party] ■

" भारत का युवा मन आत्मगौरव की खोज में "

सुनील आंबेकर
[अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री]

रों तरफ जश्न मनाया जा रहा था, फटाखे उड रहे थे, मानों दीपावली का त्यौहार हो। की सडकों पर 20–20 क्रिकेट मैच जीतकर भारतीय टीम का जोरदार स्वागत हो रहा था सारा देश अपने टी.वी. के परदे पर उसे देख था। नौजवानों की खुशी इतनी थी कि वह नहीं समा रहे थे। ठीक, ही तो था, भारत की जीत जो हुई थी। अपने भारत पर गर्व करने का मौका जो था। वैसे "लगान" की या 'चक दे या' की काल्पनिक जीत से भी वह ने खुश हुये थे फिर यह तो सच्चाई थी।

युवाओं को मायूसी तो कई बार मिली भी थी। उन्होंने कभी म्पिक की हार देखी थी, तो कभी और कहीं। नई उडानों ह सोचना चाहते, सपना भी देखते परंतु उन्हें बनी–बनायी से नियति समझकर समझौता करने की सीख दी जाती । उन्हें पता था कि सूचना क्रांति में भारत कुछ आगे बढा है और कुछ बहुत थोडा जिस पर वह गौरवान्वित अनुभव कर सके। वह तो चाहता है कि अपने देश के नाम पर सर उठाकर दुनिया में चलें। उसे अच्छा नहीं लगता कि हमारा देश किसी भी बात में दुनियां के देशों की कतार में पीछे खड़ा हो। लेकिन उसे तो पता ही नहीं, मेरा भारत कैसा था,कैसा है। वह जानना ता है कि वह कौन है। उसके पुरखों ने क्या पराक्रम किये जिस पर गौरव करें ?

गुलामी की कहानी, कमजोरी, मजबूरी तो उसने खुब सुनी है। आज भी वह कई ऐसे प्रंसगों को अनुभव करता है जो उसे अपमान से लगते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भाषा में कुशल होकर भी जब कहीं केवल अंग्रेजी की कमजोरी से पीछे रहता है, तो स्वाधीन हिंदुस्तान में उसे असहज, अपमानित सा लगता है। अंग्रेजों के समय तो गरीबी, लाचारी की कई कहानियाँ उसे पता हैं, परन्तु आज भी अपने देश में लाखों लोग दो वक्त की रोटी के लिये मजबूर स्थिति में देखकर लज्जा होती है। इतिहास की कई धटनायें आज हमें याद है। लेकिन कई बातें इस तरह कम करके समझायी जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं । युवा तो अपमान के प्रंसग विस्तार से समझना चाहता है ताकि वह स्मृतियां उसे झकझोर कर रख दें। जिससे प्रेरणा पाकर कुछ करने का दृढ़ संकल्प वह कर सके।

अंग्रेजों ने 1857 के पश्चात दिखायी कुटिलता एंव क्रूरता को समझना है। तभी तो हमारे वीरों का महत्व ध्यान आयेगा। मुगलों द्वारा हमारी संस्कृति, देव–देवताएं एवं महिलाओं के साथ किये गये भंयकर अत्याचार की कहानी सुनकर आज भी मन कांप उठे, तब महाराणा प्रताप, शिवाजी के साथ हिम्मत से जुटे एवं समर्पित भारतीय युवाओं की बलिदान गाथा समझ में आयेगी।

देश में ऐसे कई प्रसंग आये कि समझने वाले युवाओं को अपनी जवानी पर तरस आया, लेकिन कई युवाओं की अज्ञान वश यह संवेदना ही कमजोर रह गयी।

स्वाधीन भारत में कश्मीर में कई अत्याचारों का सामना करते हुये लाखों लोगों को भागना पड़ा, हजारों बहनों का अपमान हुआ। हम कुछ खास नहीं कर पाये, यह सोचकर ही लज्जा होती है। 1962 में चीन ने आक्रमण किया, हमारे नेताओं की मुर्खता के कारण कई जवान मारे गये व हमारी मातृभूमि का कुछ हिस्सा वह कब्जा कर गये, जो हम अभी तक वापस नहीं ले पाये।

समझ नहीं पा रहे है, कैसे हमारे आखों के सामने देश बंट गया, लाखों लोग मारे गये, हजारों मां–बहने प्रताड़ित हुई बांगलादेश व पाकिस्तान में आज वहां बसे हिन्दुओं पर अत्याचार की श्रृंखला जारी है। क्यों भारत–पाक क्रिकेट मैच को युद्ध की तरह देखते है लोग ? वह जीतकर इतने अपमानों का कुछ कर्जा उतारना चाहते है? 1971 की जीत या कारगिल की विजय उसे इस अपमान से कुछ मुक्ति जरूर दिलाता है, इसलिए वह इसे धूमधाम से मनाना चाहता है।

उसे पता है हमें कानून के साथ चलना चाहिए, लेकिन वह कभी कभी कानून को तोड देना चाहता है, जो हमारे समाज के अनुकूल नहीं हैं। जैसे महात्मा गांधी अंग्रेजों के समय कानून भंग करते थे, वह आज के अंग्रेजियत से भरे कानूनों एवं विदेशियों के प्रतिक ढांचों को समाप्त करना चाहता है। बाबरी

ढांचे का समाप्त होना महज एक सयोग या अपघात नहीं था, वह उसकी नियति थी। युद्ध भूमि के बिना किसी को मारना धर्मानूकूल नहीं। यह वह जानता है व उसे पालन भी करना चाहता है। परन्तु गोधरा में जलाये गये लोगों से उसे अपनापन हुआ है, एवं अब अपमान न सहने का मन उसने बना लिया है। न जाने उसे तब क्या–क्या याद आता है, शायद स्वाधीन भारत में चली गोहत्या भी।

उसे याद है कि आज भारत की सीमा के अन्दर कैसे करोडों घुसपैठी आते हैं। स्थान–स्थान पर आतकवादी कैसे विस्फोट करते हैं। कंधहार की घटना जिसमें हमारे नागरिको के बदले में हमने खूंखार आंतकवादियो को छोडा था या बांग्लादेश की सीमा पर हमारे सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ) के जवानों की हत्या भी उसे याद

रखना जरूरी है। उसे पता है कि किसी को जिंदा जलाना ठीक नहीं, परन्तु मिशनरी ग्राहम स्टेन्स के हत्यारों का वह उतना विरोध नहीं कर पाता क्योंकि उसे स्मरण मे है, मिशनिरियों की वह कुटिल गतिविधियां। यहाँ की संस्कृति एवं मिट्टी से भोले–भाले लोगों को तोडने का मिशन का सच्चा स्वरूप वह जान जो गया है।

मैं कभी–कभी सोचता हूं, क्या यह समृद्धि की ललक, नई मुक्त शैलियां यह सिद्ध कराने की मानसिकता तो नहीं कि हम भी कुछ कम नहीं, हम भी मुक्त है।

गुलामी की हर जंजीर को तोडना, यह युवाओं का सकल्प हो रहा है, इसलिए आत्मगौरव की हर बात वह ढूंढ रहा है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या उससे जुडे तत्व उसे इसलिए अच्छे लगते है कि वह अपनी आत्म गौरव की बातें ढूंढने का उचित माध्यम उसमें पाता है। विद्यार्थी परिषद की गतिविधि में इस पुराने अपमान के बोझ से कुछ मुक्ति का अनुभव मिलता है। कुछ रास्ता मिलता है,स्वाभिमान से जीने का।

भारत के हर अपमान का करारा जबाव देने की इच्छा जागृत हो रही है। संगणक नही मिला तो परम सगणक, दूसरी सेनाओं के मुकाबले में मिसाइलों के अनुसंधान,सेटेलाईट की श्रृंखला यह सारे युवाओं के परिश्रम का परिचम है।

सडक योजना में क्राति लाने वाले अटल जी या वैज्ञानिक अब्दूल कलाम उसे गौरव लाने वाले लगते है। कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स पर उसे नाज होता है।

देश के वामपंथियो ने रोजी–रोटी की बात की लेकिन शाति छीन ली, धर्म छीन लिया, उनकी यूनियनों ने उसे यूनियन का नौकर बना दिया।

कांग्रेस की ढीली ढाली नीति ने उसे स्वराज देने का श्रेय तो लिया परंतु उसके क्रातिकारी इतिहास को दबा दिया तथा जिसकी परिणति देश के विभाजन में हुई। समझौता वादी नीति ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की हद कर दी बिल्कुल वैसे, जैसे विभाजन पूर्व की थी। उसने आजादी के 60 वर्ष के अन्दर ही पुन: एक विदेशी नेतृत्व देश को प्रदान किया।

लेकिन देश मे एक लहर उठना जरूरी है जो ऐसे हर अपमान को समाप्त कर देगी। इसलिए देश के हर युवा को देश के आत्म गौरवपूर्ण हजारों वर्षो के इतिहास को समझना पडेगा। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि इतिहास पीकर तृप्त हो जाओ फिर आत्म गौरव के साथ वर्तमान से भविष्य की ओर बढो। अब बदलना होगा कि हम केवल IT Solutions की कम्पनियां खोलेगें,अब हमारा नारा होगा 'भारत–Solutions for All'.

उसके लिये तीव्र गति से हमे अपनी अन्दरूनी समस्याओं पर समाधान ढूढने पडेंगें।

बैसाखियों को फेंककर दौडना होगा, आगे आगे निश्चित ही पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए। ■

राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष तेज करने की जरूरत

–संजीव कुमार सिन्हा

"...ब चीजों की व्यवस्था हो गई है। शराब, कार, रुपए, पोस्टर, मैनपावर। चुनाव के लिए जो भी चाहिए, उसकी व्यवस्था हो गई है। कोई दिक्कत नही है।"

"...सभी खर्चे महत्वपूर्ण है। चालीस लडके दो ...मे रह रहे है, जिसे मैंने किराया पर लिया है। इ... ...लिए मैंने रसोइया भी रखा है।"

"...मैने 4.5 लाख रुपए देकर एनएसयूआई का टि... खरीदा है।"

–यह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव मे एन... ...यूआई के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी का कथन है।

...सितम्बर, 2007 भारतीय छात्र आंदोलन के लि... ...एक काला अध्याय साबित हुआ। इस दिन सीएनएन आ... ...एन–कोबरापोस्ट के वीडियो फुटेज से पूरा देश सन्न हो उ... जिसमे एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने बडे इत... ...मान से उक्त बातें बता... लेकिन कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई पर इसका कोई असर नही पडा। और ऐसा होना लाजिमी ...था। सब जानते है कि एनएसयूआई का

इतिहास ऐसी घटनाओं से भरी पडी है। ज्यादा पुरानी बात नही है। सन् 1999 के डूसू चुनाव मे एनएसयूआई के सहसचिव पद के प्रत्याशी ने फर्जी जाति प्रमाण–पत्र देकर नामाकन लिया था। इसी तरह सन् 2001 में एनएसयूआई के सचिव पद के प्रत्याशी का नामांकन गलत अंक–पत्र के आधार पर हुआ था। झूठ, फरेब, गुण्डागर्दी यह एनएसयूआई की राजनीति है। यही तो "कांग्रेसी कल्चर" है।

इस साल 7 सितम्बर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव संपन्न हुए और 8 सितम्बर को इसके परिणाम आए। चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे। विद्यार्थी परिषद को पराजय का मुंह देखना पडा। डूसू के चारों केन्द्रीय पदों–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव पद पर परिषद को असफलता

कभी देश के छात्र आंदोलन को दिशा देने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ आज धनबल, बाहुबल और अकर्मण्य नेतृत्व की गिरफ्त में फंस गया है। माफिया तत्व छात्र आंदोलन का अपहरण करने में जुटे है। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया है कि सही छात्र नेतृत्व कैसे उभरे। इस दिशा में छात्र समुदाय को गंभीरता से सोचना होगा।

हाथ लगी। एनएसयूआई चारों पदों पर विजयी रही। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव मे इस बार कुल 32 उम्मीदवार चुनाव मैदान मे थे। लिग्दोह कमिटी का दुरुपयोग कर परिषद के प्रत्याशियो के नामाकन रद्द कराने की साजिश रची गई। कोर्ट के आदेश को ध्यान मे रखते हुए दोबारा से नामांकन–पत्रों के जांच हुए, जिसके बाद जारी की गई सूची मे एनएसयूआई के तीन उम्मीदवारों के नामाकन पत्र सही पाए गए, जबकि विद्यार्थी परिषद के पैनल अध्यक्ष सहित तीन उम्मीदवारों का पर्चा रद्द कर दिया गया। कुल 207 नामाकन भरे गए थे, जिनमें से 172 नामाकन रद्द कर दिए गए। लिग्दोह कमिटी

की सिफारिश आनन–फानन में लागू किए जाने के कारण महज 25 प्रतिशत मतदान हुए।

एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने खुलेआम आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए धनबल और बाहुबल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। चुनाव–प्रचार के दौरान उसने टी–शर्ट, चाबी के छल्ले, डायरियां व सिनेमा के टिकट बांटकर छात्रों को भरमा लिया। दूसरी ओर दिल्ली की कांग्रेस सरकार के दबाव में दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस तरह से एनएसयूआई प्रत्याशियों के पक्ष में काम किया उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय वह कम है। विद्यार्थी परिषद् को हराने के लिए कांग्रेस सरकार ने हर उपाय अपनाए। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. गुरमीत सिंह कांग्रेस क दबाव में काम करते नजर आए।

विद्यार्थी परिषद् को हार का सामना करना पड़ा लेकिन पिछले साल जहां उसे कुल मत का 23 प्रतिशत प्राप्त किया था वहीं इस साल 28 प्रतिशत मत प्राप्त किया। सन् 2006–07 में परिषद् ने 23 महाविद्यालयों में 60 पदों पर जीत हासिल की थी वहीं इस बार 32 महाविद्यालयों में 82 पदों पर विजयी रहे।

हार और जीत लोकतंत्र के स्वाभाविक गुण है। हार से

घबराना नहीं चाहिए। हम चुनाव हारे है मनोबल नहीं। विद्यार्थी परिषद् सिद्धांत और मूल्य आधारित छात्र राजनीति में विश्वास करती है। किसी कीमत पर चुनाव जीतना परिषद् का उद्देश्य नहीं है। हमारा उदात्त लक्ष्य है। डूसू के चुनाव परिणाम से निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। इसे आत्मवलोकन का अवसर मानना चाहिए। लेकिन इसके साथ–साथ हमें अपने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष तेज करने की आवश्यकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को एनएसयूआई जैसे अवसरवादी छात्र संगठनों को सबक सिखाना चाहिए जो वर्ष भर परिसर से गायब रहते है और कुकुरमुत्तों की भांति छात्र संघ चुनाव के समय नजर आते है। हमें अपनी कमजोरी को दूर करना होगा और इस भाव को पुष्ट करना होगा कि छात्रशक्ति के आगे राज्यशक्ति की गुण्डागर्दी नहीं टिकेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की गौरवशाली परंपरा रही है। यह देश का सबसे बड़ा छात्र संघ है। यह 52 महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करता है। याद करिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का वह दौर जब इसके बैनर तले छात्रों ने देश पर आपातकाल थोपने वाले भ्रष्ट केन्द्र सरकार को ललकारा था। तब डूसू आपातकाल विरोधी संघर्श का प्रमुख केन्द्र था। सन 1975 की बात है। उस समय विद्यार्थी परिषद् के नेता श्री अरुण जेटली डूसू के अध्यक्ष थे। उनकी सक्रिय पहल पर उत्तरी परिसर में ऐतिहासिक छात्र सभा हुई थी, जिसे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने संबोधित किया था। तब छात्रशक्ति के हुंकार के सामने केन्द्र सरकार को झुकना पड़ा था। इसी तरह जब देश को भ्रष्टाचार के महारोग ने जकड़ा था तब परिषद् नेता और डूसू अध्यक्ष श्री नरेन्द्र टंडन के आग्रह पर 1988 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की विशाल छात्र सभा हुई थी।

कभी देश के छात्र आंदोलन को दिशा देने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ आज धनबल, बाहुबल और अकर्मण्य नेतृत्व की गिरफ्त में फंस गया है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की तमाम समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। चाहे सवाल शुल्क में बढोतरी का हो, सुरक्षित परिसर का हो या फिर पुस्तकालयों और लैबोरेट्री की खस्ताहाल का। चारों ओर अराजकता का माहौल है।

सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि सार्वजनिक रूप से बेनकाब हुए एनएसयूआई का प्रत्याशी आज डूसू उपाध्यक्ष बना बैठा है और एनएसयूआई सारी नैतिकता ताक पर रखकर चुप्पी साधी हुई है। वहीं हर छोटी बात की खबर लेने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन कांग्रेसी सरकार के दबाव के चलते पंगु बना हुआ है। इस प्रकरण से यह साफ जाहिर है कि आज माफिया तत्व छात्र आंदोलन का अपहरण करने में जुटे है। यह चिंता का विषय है। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया है कि सही छात्र नेतृत्व कैसे उभरे। इस दिशा में छात्र समुदाय को गंभीरता से सोचना होगा। ■

Special Interview

Rama Sethu a man-made structure : Dr Badrinarayanan

Dr Badrinarayanan is a well-known Geologist who had been the director of the Geological Survey of India. He was also former coordinator of the survey division of the National Institute of Ocean Technology, Ministry of Earth Science, in Chennai.

As a geologist who has done studies on the geological aspects of the area where Sethu Samudram Canal Project is being undertaken, Dr. Badrinarayanan puts forth some interesting findings on the area.

As a geologist, how do you describe Ram Sethu? Is it a man-made structure or natural formation?

It is not a natural formation; the top portion of it appears to be a man-made structure. To understand what I am saying from the geological point of view, you have to get to know several things. What is known as Adam's Bridge is originally a natural grade divide separating the Bay of Bengal and the Indian Ocean to the south. So, the geological aspects are different on either side. About 18,000 years ago, we had Ice age when the sea level was lower by 130 metres than what it is now. Due to de-glaciations, the sea level rose. Around 7,300 years back, there was major flooding and the sea level rose to 4 metres more than what it is today. This has been verified by several researchers throughout the world. But the bridge that connects India and Sri Lanka is different; it is not just a sand dune.

Have studies been done on this particular phenomenon?

We (Geological Survey of India) were asked to carry out surveys for locating the Sethu Samudram Canal project by the project authorities in 2004-05.

Any startling revelations?

When we reached near Adam's Bridge, there was sudden rise in the land level. From about 10-12 metre, it rose one metre to half a metre. So, our vessel could not go and survey the area. In some areas, we did survey using small boats. The northern side of Adam's Bridge is the rough Palk Bay, which is prone to periodic cyclonic storms, and the tranquil southern side is the Gulf of Mannar, which is unpolluted and pristine. Corals grew in the tranquil Gulf of Mannar but not in the turbulent Palk Bay as they grow only in tranquil waters. There are about 21 islands full of corals in the Gulf of Mannar side but not even a single coral on the northern side of Adam's Bridge. I would say no proper geological survey was done in the area. Normally before any major engineering project, GSI conducts engineering geological study, geological study, geo-tectonic study, Seismic study, etc so that we will know whether the project is safe or not.

You mean no such studies were done before this project?

Earlier, GSI had done some drilling but only at the deeper level of about 180-200 metres, but they have not mentioned anything about what was happening at the top portion. We did a study from NIOT on our own connecting between Rameswaram and the international waters. We did around 10 bore holes along the Adam's Bridge

alignment. Four of the bore holes were along the islands (where sands go on shifting) and six in the water.

Everywhere, after top 6 metres, we found marine sands on top and below that was a mixed assemblage of corals, calcareous sand stones, and boulder like materials. Surprisingly below that up to 4-5 metres, again we found loose sand and after that, hard formations were there.

How do you explain the presence of loose sand?

It shows the structure is not natural. I will explain. Corals are found only on rocks and such hard surfaces. Here, below the corals and boulders, we are getting loose sand, which means it is not natural. And, on top of the loose sand, which was formed when the sea level was low, our divers found boulders. Boulders normally occur on land and they are a typical riverine character.

Does that mean the boulders were brought there from somewhere?

That is exactly what I am saying. The boulders are not in-situ. They are not a marine local formation. We feel somebody dumped the boulders to use it as a causeway. The boulders on top of the loose sand are transported to that place. As they are found above loose sand, it is quite obvious that they were brought and dumped there by somebody.

How old were the boulders?

I told you earlier those 7,300 years ago, sea level was 4 metres above what it is today. In Rameswaram, Pamban, Tuticorin, etc, we see old corals on the land, and they are not raised by any geological process. It happened because sea level was higher (at the time they were formed). We did dating on them and found that they are 7,300 years old. From 7,300 to 5,800 years ago, the sea level was high. From 5,800 to 5,400 years ago, the sea level was low. Again, from 5,400 to 4,000, the sea level was higher by 2 metres than what it is today.

That is why we are getting two sets of corals at two levels. Dr P K Bannerji has carried out a lot of studies on the raised corals and his papers have appeared in reputed international scientific journals. His arguments are backed by very good scientific data.

So, either between 5,800 to 5,400 years ago, or (some time since) 4,000 years ago, somebody appeared to have brought all the boulders and dumped them there. All the aerial pictures show that Adam's Bridge is 2 to 3 kilometres wide. On the eastern side, it is high. So, anyone could take advantage of the raised portion and must have dumped these boulders so that he could cross the bridge.

How do the boulders look, and from what were they made?

The shape of the boulders and the type of material clearly indicate that this is a man-made structure. We saw similar rocks on Rameswaram islands and also in Pamban. On either side of the railway bridge, you can see these formations as well as the raised corals. There are indications of quarrying also there. All these things lead us to believe that 2 to 2.5 metres of packed rubble or material appears to be a modern day causeway. For 30 km, nobody dumps materials like that. Obviously, it was dumped to use it to cross the sea. Moreover, they are compact and light. It is also quite obvious that the boulders were used to cross over because in all the bore holes we made in the entire stretch of Adam's Bridge, we saw the same material. It appears like a rock filled structure. If it is a geological phenomenon, you will find the oldest formation below and the newer ones on top. I would rather call it an anthropogenic (pertaining to the effect of human beings on the natural world) causeway rather than a bridge.

What else have you learnt from the studies you have conducted along Ram Sethu?

We have found that geologically and geo tectonically, this area is very sensitive. Many people are not aware of it. All around the north, there are spots where there is very high temperature below.

When we drilled, we encountered hot springs of 60 to 70 degrees Celsius. Whenever there are earthquakes in Sri Lanka, we get the vibrations in the Indian side also. That means a major fault is running there and it is very sensitive. This area is also known to have earth quakes and they had happened one or two centuries back. To the north and the south, there are indications of old volcanoes.

Because of these hot springs and presence of volcanic zones, do you feel if disturbed, it will affect the equilibrium of the entire area?

What you said is correct. That is why, before venturing into anything, you have to make a comprehensive study. This area has attained some sort of equilibrium over many centuries, and all the drilling and blasting of rocks may activate the fault and may trigger seismic activity or earth quakes. It may also trigger other events, which may be very detrimental. That is because the hot water from the north, which is blocked by the Adam's Bridge, will come to the south and will disturb the coral islands. The result will be the destruction of the corals. Not only that, whenever there is a major tsunami or cyclones in the Bay of Bengal, it is blocked by the so called bridge.

Out of 18 depressions in the Bay of Bengal at least six turn into cyclones. When we interviewed the tsunami expert Dr T S Murty, he said if not for the bridge, the entire southern part of Kerala would have been affected badly. Yes, it would have completely affected the entire south India. We were the people who suggested it. We had done a study, of course not knowing tsunami is coming, and felt the structure will prevent the Tuticorin area, the southern part of Kerala and all the coral islands from getting affected. The calm tranquil water in the Gulf of Mannar full of coral islands is because it is protected all around.

Why do they want to destroy it when nature has blessed us with something so beautiful?

This is the first declared marine national park in the country. Another point I want to make is, some dams trigger earthquakes. There is a possibility it can happen here also. So, it is prudent on part of the government to study all these aspects before taking a major decision.

Do you feel the construction of Sethu Samudram project was initiated in a hurry without conducting proper study?

I think so. This portion is not like any sand dune. This is a very sensitive heat flowing area. I feel the Geological Survey of India should be asked to do a survey.

Was the Geological Survey of India not asked to do a study on this project?

No. Nobody has carried out any survey at all. We only did a survey to locate the alignment. So, but what is needed is a comprehensive study. What has been formed over centuries by nature cannot be disturbed. In foreign countries, even a hundred-year-old structure is preserved and this looks like it is thousands of years old. No doubt such a canal is essential but not at the cost of nature. We are definitely for progress but our progress should be sustainable. ■

(Courtesy: Rediff.com)

"Ramanama is for the pure in heart and for those who want to attain purity and remain pure"

- Mahatma Gandhi -

परिचर्चा

धर्म के आधार पर आरक्षण : उचित या अनुचित?

अकांक्षा उपाध्याय, पत्रकारिता छात्रा

धर्म के आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं है। इस तरह से किए जाने वाले भेदभाव को ठीक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिसे व्यवस्था को हम समाज में भेदभाव कम करने के लिए लाना चाहते हैं, उससे और भेदभाव बढ़ेगा, साथ में समाज में कटूता भी बढ़ेगी। बात सिर्फ शिक्षण संस्थानों तक सीमित क्यों रखें, कहा जा रहा है कि अब नौकरियों में भी आरक्षण बढ़ाया जाएगा, नीजी संस्थानों में भी आरक्षण देने की बात जारों पर है। क्या वोट की राजनीति करने वाले नहीं जानते, सत्ता पाने के लिए वह एक नीहायत ही गलत तरह की व्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं। जिसे किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

हृदेश भंडारी, छात्र, दिल्ली

हमारे देश में आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। यह अच्छा नही है। हमारे देश में कई धर्म–सम्प्रदाय के लोग हंसी–खुशी रहते हैं। विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता है। यदि मजहब के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा तो यह हमें बांटेगा। हम एक रहकर भी एक नहीं रह पाएगा। एक बार यही काम अंग्रेजों ने आजादी के समय किया था। जिसका परिणाम देश विभाजन था। अब अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों के रहे–सहे काम को पूरा करने का जिम्मा हमारे ही देश के कुछ माननीय नेताओं ने उठा लिया है। मुझे लगता है, ऐसे नेताओं को अपने इस कर्म पर शर्म आना चाहिए।

विवेक शर्मा, पत्रकारिता छात्र, नोएडा

मुझे आरक्षण देने में कुछ गलत नहीं लगता। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा भाई है। इस नाते हमारा कर्तव्य बनता है, जो लोग राह में पीछे रह गए हैं, उन्हें हम मदद करें। लेकिन जाति या मजहब के आधार पर आरक्षण देना, मुनासिब नहीं है। आरक्षण का आधार यदि गरीबी रेखा हो तो यह सबसे अच्छा है। इससे किसी को शिकायत भी नहीं होगी और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंच सकेगी। चूंकि उस जाति और मजहब के लोग अधिक संख्या में गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिसे सरकार मदद देना चाहती है। इस तरह सरकार का मकसद भी पूरा हो जाएगा।

देवेन्द्र कुमार, छात्र, दिल्ली

भारत एक ऐसा देश है, जिसमें कई धर्म, जाति के लोग रहते है। कई तरह की खुशबुओं को इसने खुद में समेटा है। यदि मजहब के आधार पर यहां आरक्षण दिया गया तो सभी धर्म के लोगों को आरक्षण देना होगा। जो कि शायद उचित नही होगा। और कुछ हद तक संभव भी नहीं होगा। हो सकता है, एक समय ऐसा भी आए जब थोड़ा–अधिक सभी लोगों को आरक्षण मिले। जिस छोटे से तबके को आरक्षण किसी कारणवश नहीं मिल पाए, उसे लोग 'सवर्ण–दलित' कहें। खैर यह तो व्यग्य की बात है, लेकिन सच पूछा जाए तो मैं किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हूं।

जितेन्द्र गौतम जीतू, टाइम इन्स्टीट्यूट फॉर मैनेजमेन्ट, दिल्ली

आरक्षण देने में कोई बुराई नहीं है। सैकड़ों वर्षों तक जिस समाज को सवर्णों ने अपने पैरों के नीचे रौंदा है। आज जब वह आरक्षण की मदद से उनके साथ आकर खड़ी हुई है, तो सवर्ण समाज में खलबली सी मच गई। वह इस परिवर्तन को पचा नहीं पा रहे हैं। यही मुश्किल की जड़ है। समाज में जो इतना परिवर्तन आज हम देख रहे हैं, उसका सारा श्रेय आरक्षण को जाता है। आज यदि दलित या किसी पिछड़े पर कोई अत्याचार करता है तो वह उसके खिलाफ आवाज उठाता है, चुपचाप बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि अब उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, उसकी अपनी जाति–बीरादरी के लोगा ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं, उसकी बात अब सुन कर अनसुनी नहीं की जाएगी।

इन्द्र वशिष्ठ, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा

यदि हम वास्तव में पिछड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं तो हमें आरक्षण की मदद से नहीं उनकी दूसरे

से सहायता करनी चाहिए। यदि केन्या और दक्षिण
का जैसा देश क्रिकेट खेलता है तो

मतलब यह थोड़े ही ना है कि
को बाउण्ड्री छोटी कर देनी चाहिए
उनके 50 रन को 100 रन मान लेना
ए। यह सहायता का नहीं, हतोत्साहित
का तरिका है। किसी को हम
कि तुम पिछड़े हो इसलिए तुम्हें हम कोटा दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं एक स्वाभिमानी इंसान का स्वाभिमान भी
होगा। ऐसे में ज्यादा अच्छी स्थिति यह होगी कि हम
के पढ़ाने–लिखाने पर अधिक ध्यान दें और उस वक्त उन्हें
रियायतें दे सकते दें। लेकिन तमाम तरह की प्रतियोगी
शाओं में किसी प्रकार का आरक्षण जाति और मजहब के
ार पर देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ■

प्रस्तुति– रवि टोंक

परिचर्चा

भारत में अल्पसंख्यक कौन ?

इस विषय पर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' द्वारा परिचर्चा आयोजित है। इस परिचर्चा में पाठकों के विचार आमंत्रित है। अधिक से अधिक 500 शब्दों में अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखकर या टाइप कराकर पासपोर्ट आकार के अपने एक चित्र के साथ 15 नवम्बर तक प्रेषित करें। प्राप्त उत्तर नवम्बर– दिसम्बर अंक में प्रकाशित किये जायेंगे।

सम्पादक, 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति
136, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली–110001

OBITUARY

Shri Jana Krishnamurthy

Former BJP national president, and former Union Minister K. Jana Krishnamurthy breathed his last on September 25, 2007 at a private hospital in Chennai following a prolonged illness.

He was 79 and is survived by wife, two sons and three daughters. Born on May 24, 1928 at Madurai in a family of lawyers, he practised as an advocate in Chennai for over ten years, before he was attracted to the RSS. He later became its Pranth Baudhik Pramukh of RSS. On instructions from the then RSS chief Guruji Golwalkar, he enrolled himself as a member of the Jana Sangh in 65. He started his political career as a RSS volunteer in 1940 and became the first south Indian president of BJP in 2001. He became Union Law Minister in 2003.

An admirable leader, advocate, social worker and a statesman who served for the strengthening of India's democracy. He toiled everyday in the dust of the nation's politics, but never allowed the dirt to influence his intrinsic cleanness of financial integrity. Jana Krishnamurthy remained for most of his life a low-profile worker of the Sangh Parivar. Such was the man's simplicity that even though he held important posts, on his visits to Delhi, Shri Krishnamurthy lived in the party offices just like other full-timers. He was a man who was at his best implementing orders.

Shri Jana Krishnamurthy must be admired for his ability, courage, detachment and confidence. Chhathrashakti salutes Janaji. His passing away is really a great loss to the cause of national awakening. We send our heartfelt condolences to all his family members and also to the large family of his friends and admirers. ■

रामसेतु आंदोलन और राष्ट्रीय मीडिया

– आशुतोष भटनागर –

कुछ समय पहले सामाजिक–धार्मिक कोनों से उठी रामसेतु विध्वंस पर रोक लगाने की मांग ने अब न केवल राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है बल्कि अमेरिकी नाभिकीय समझौते पर उठे बवंडर से हिली केन्द्र सरकार को एक और झटका दिया है।

वामपंथियों ने हालांकि नाभिकीय समझौते के मुद्दे पर कोई निष्कर्ष निकलने से पहले ही राम सेतु मामले पर अपना बयान जारी कर दिया है । द्रमुक नेता करुणानिधि ने राम के बारे में बयान देकर राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है और उनकी राजनैतिक प्रतिद्वंदी जयललिता ने यह मुद्दा लपक लिया है। जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगनादेश देकर रामसेतु विध्वंस पर फिलहाल रोक लगा दी है ।

यदि सतही तौर पर नजर डालें तो यह सारा घटनाक्रम केवल बीस दिन तक चला लेकिन इसकी भूमिका बहुत पहले से बन रही थी । 2 जुलाई 2005 को सेतु समुद्रम परियोजना के उदघाटन से पूर्व ही इसके विरोध के आधार तय हो गये थे। सरकार ने परियोजना के उदघाटन में जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई वह संदेह पैदा करने के लिये अपने आप में पर्याप्त थी। साथ ही सरकार ने इस संबंध में उत्पन्न भ्रम और संदेह को दूर करने और वास्तविक और तथ्यपूर्ण विरोध को किसी सहमति तक लाने के बजाय संघर्ष का रास्ता ही अपनाया ।

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जब राम, रामकथा और रामसेतु को नकारने वाला हलफनामा दाखिल किया तो देश में तूफान खड़ा हो गया। 12 सितम्बर को विश्व हिन्दू परिषद के आह्वान पर देशव्यापी चक्का जाम को प्रचण्ड समर्थन मिला तो सरकार की आंखें खुली। सोनिया गांधी के कथित हस्तक्षेप के बाद सरकार ने अपना हलफनामा वापस ले लिया। डी एम के अपने रुख पर अड़ी रही और वामपंथी दल उसके समर्थन में उतर आये। उपरोक्त सारे घटनाक्रम में राजनीति हुई, और जम कर हुई। राजनैतिक दलों को यह करना ही था। सरकार का हलफनामा दाखिल करना और वापस लेना, दोनों ही गठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली के निकृष्टतम उदाहरण बने। लेकिन सरकार को जैसे ही जनाक्रोष का भान हुआ, उसने स्थिति पर नियंत्रण की कवायद शुरू कर दी।

अंतर्विरोधों की मिसाल बन चुकी यूपीए सरकार की राजनैतिक मजबूरियों ने उसे इस प्रकार का अस्वाभाविक व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया । उसकी नींद तभी खुली जब 12 सितम्बर को एक साथ पूरा देश ठप हो गया।

लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि देश का समूचा मीडिया भी इस ज्वलंत मुद्दे पर कुम्भकर्णी नींद सोया रहा। 12 सितम्बर को जम्मू से लेकर रामेश्वरम और कच्छ से लेकर नगालैंड तक देश भर में बारह लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उमड़ उठे और पांच हजार से ज्यादा जगहों पर लगे जाम से पूरा देश एकबारगी ठहरही गया। कुछ चैनलों को जहां इ स्टोरी नजर आयीं वहीं अधिकांश मीडिया के खबरची उस दिन भी इस तरह के बंद से लोगों को होने वाली परेशानी की ही चर्चा करते नजर आये। अगले दिन के अनेक समाचार पत्रों में भी चर्चा बंद और उससे हुई तकलीफों की ही थी, मूल मुद्दे की नहीं।

यह कहना कठिन है कि मौके की नजाकत को समझने की तत्परता दिखाने के लिये राजनीतिज्ञों की प्रशंसा की जाय अथवा तूफान के गुजर जाने के बाद भी उसकी तीव्रता महसूस न कर पाने के लिये मीडिया की आलोचना, लेकिन यह सच है कि मुद्दे की तपिश का जहां सरकार को तुरन्त अहसास हो गया वहीं मीडिया हलफनामा वापस लिये जाने तक गफलत में रही। हलफनामा वापसी के बाद मीडिया चौकन्नी हुई। चैनलों के दतरों में हलचल हुई, कारिंदे प्राइम टाइम में चर्चा के लिये विशेषज्ञों के उत्खनन में जुट गये।

मीडिया के साथ यह दुर्घटना उसके अपने पूर्वाग्रहों के चलते हुई। मीडिया गुरुओं के दिमागों पर हावी सेकुलर विमर्श के चलते उनके भीतर यह पैठ गया था कि भाजपा के राजनैतिक रुप से पिछड़ने के साथ ही हिन्दुत्व का मुद्दा दम तोड़ गया है। उन्होंने सेफ्रोलॉजी के गर्भ से निकले चुनावी आंकड़ों की तो जुगाली की लेकिन देश के आम आदमी के मन में बसी आस्था का आकलन नहीं कर सके।

राजनीतिज्ञों की समझ में जहां यह बात तुरंत आ गयी कि राम के नाम पर जब बात चल निकली है तो इतनी जल्दी सिमटेगी नहीं। राम से जुड़ा मुद्दा गरमाया है तो राम सेतु पर ही नहीं रुकेगा, राम मंदिर तक जायेगा। लेकिन मीडिया को समझने में देर लगी। जिन्होंने मुद्दे की गरमाहट को महसूस भी किया उन्होंने अपनी वैचारिक निष्ठाओं के बोझ तले दबे होने के कारण तथ्यों को सामने लाने के बजाय उसे नकारने अथवा

रअंदाज करने का पैंतरा लिया।

मीडिया के इस वर्ग ने अपना बारंबार आजमाया हुआ ुखा एक बार फिर बाहर निकाला है । पहले दौर में वे इसकी फलता के प्रति आश्वस्त भी हैं। नुस्खा है मुद्दे को समाचारपत्रों सिरे से ही गायब कर देना या कम से कम जगह देना ताकि ोगों को यह संदेश जाये कि इस पर कोई सामाजिक प्रतिक्रिया ही है। इसे और पुष्ट करने के लिये वे विरोध में आने वाले ायानों और टिप्पणियों को अतिरंजित करके छापते हैं ताकि ाठक का ध्यान विषय के केन्द्र से हट कर परिधि पर टिक जाय।

राम मंदिर आंदोलन और कारगिल के समय वे इसे पहले भी आजमा चुके हैं। कारगिल युद्ध के समय घुसपैठियों के िरुद्ध कार्रवाई करते हुए सैनिक जब शहीद हो रहे थे तो अपने ाप को राष्ट्रीय मीडिया बतानेवाले समाचार पत्र जंतर–मंतर पर धरने पर बैठे कुछ पेशेवर धरना देने वालों की फोटो छाप रहे थे जिनकी तख्ती पर लिखा था– युद्ध नहीं रोटी चाहिये। पोखरण में जब दूसरी बार बुद्ध मुस्कराये थे तो भी कुछ इसी तरह के नारे उछाल कर असली मुद्दे पर परदा डालने की कोशिश हुई थी। राम सेतु के मुद्दे को भी इसी तर्ज पर भटकाने की कोशिश हो रही है।

ऐसा नहीं है कि राम सेतु का मुद्दा अचानक आ खड़ा हुआ है। पिछले दो साल से भी ज्यादा से विभिन्न मंचों से यह मुद्दा उठाया जा रहा था लेकिन मीडिया ने इसकी गंभीरता को लगातार नजरअंदाज किया। तमिलनाडु के मछुआरों ने जब इसका विरोध किया तो मीडिया ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जब वहां के धर्माचार्यों ने इसे आपत्तिजनक बताया तब भी मीडिया खामोश रहा। न्यायालय का मुकदमा स्थानीय अदालत से चलते–चलते सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया लेकिन मीडिया के कान पर जूं नहीं रेंगी। शंकराचार्य सहित देश भर के 3800 से ज्यादा धर्माचार्य दिल्ली में आये और दो दिन तक चीख–चीख कर अपनी बात कहते रहे, राष्ट्रीय मीडिया की खामोशी नहीं टूटी। पचास हजार से ज्यादा लोगों ने रामलीला मैदान में आकर प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय मीडिया में पहले पेज की खबर नहीं बन सकी। यह सभी अवसर ऐसे थे जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता और सरकार की बदनीयती को उजागर करता तो समाज का मीडिया पर विश्वास जगता। यह ठीक है कि बाजार में बैठे मीडिया के लिये समाज अनावश्यक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि भारत में आज भी समाज जिंदा है, अपनी जड़ों से जीवन प्राप्त कर रहा है। ऐसे समाज की आस्था के प्रश्नों को नकार कर बाजार की पूंजी पर इतराने वाला मीडिया बहुत लंबे समय तक अपनी प्रासंगिकता बनाये नहीं रख सकेगा। ■

(साभार : हिन्दुस्थान समाचार)

Bhagvad Geeta be made national 'dharma shastra': Allahabad High Court

In a judgement,the Allahabad High Court has said that Bhagvad Geeta should be made the national 'dharma shastra' of the country and it should be considered a fundamental duty of all citizens to follow the 'dharma' as propounded by it.

"As India has recognised its national flag, national anthem, national bird, national animal and national flower, Bhagvad Geeta may be considered as national (rashtriya) dharma shastra," Justice S N Srivastava has observed.

In an order dated August 30, he said the Bhagvad Geeta had greatly inspired those involved in the freedom struggle and continues to inspire people from all walks of life.

"Hence, it is the duty of every citizen of India under Article 51-A of the Constitution of India, irrespective of caste, creed or religion, to follow dharma as propounded by the Geeta," he said.The observation came while hearing a petition filed by Shyamal Ranjan Mukherji, a priest of Gopal Thakur Mandir in Varanasi.

Says Allahabad High Court lawyer, Krishna Shukla, "The Bhagavad Gita was an inspiration to all who took part in the struggle for India's independence and the preaching in the holy book are for the common man, and not for any particular caste or creed."

यौन शिक्षा के मुद्दे पर अभाविप ने जताया विरोध

आगरा

केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में यौन शिक्षा को लागू करने के खिलाफ अभाविप ने हाल ही में पुतला फूंककर विरोध जताया। भारी संख्या में परिषद् कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर से होते हुए बाईपास चौराहे पर जाम लगाया और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। अभाविप प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यौन शिक्षा भारत को खोखला करने की साजिश है। परिषद् के सदस्य मनोज राघव के मुताबिक इस तरह की शिक्षा समाज के हित में नहीं रहेगी। इससे सेक्स का खुला प्रचार बढ़ेगा और युवा मानसिक विकृतियों से ग्रस्त हो जाएंगे। परिषद् कार्यकर्ता अमित दिवाकर के मुताबिक इस शिक्षा से अपराधों में बढ़ोत्तरी होगी एवं अव्यस्क लड़के लड़कियों के गुमराह होने का खतरा बढ जाएगा।

लखनऊ

हाल ही में यौन शिक्षा के लिए छपी पुस्तकों पर विचार के लिए रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक सुर जमकर खिलाफत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विधान परिषद् में शिक्षक दल के नेता और संगठन के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि यौन शिक्षा से शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालयों में अनुशासन व्यवस्था ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और ऐसे में विद्यालय की दीवारों पर सूक्तियों की बजाय किताबें घिनौने रेखाचित्रों से भर जाएंगी। कार्यकारिणी ने कहा कि यूनेस्कों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं हैं। शिक्षक संघ ने यह भी कहा कि माध्यममिक शिक्षा परिषद् द्वारा यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने एवं इस विषय की पुस्तकें प्रकाशित करने से पहले शिक्षकों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। शिक्षकों ने रोश व्यक्त करते हुए इस अवसर पर कहा कि यौन शिक्षा के नाम पर अश्लीलता का पाठ पढ़ाने वाली यूनेस्को की इन किताबों का विद्यालय में प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा और अधिकारियों के कार्यालयों के समक्ष ऐसी पुस्तकों की होली जलाई जाएगी।

मेरठ

सेक्स एजुकेशन के विरोध के स्वर मेरठ में भी सुनाई दिये। अभाविप कार्यकर्ताओं ने मेरठ कालेज के बाहर प्रदर्शन कर केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह का पुतला दहन किया। अभाविप के विभाग संगठन मंत्री संजय सिंह के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर छात्रों ने कहा कि सैक्स एजुकेशन किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दी जाएगी क्योंकि इससे गुरु शिष्य परंपरा तार तार हो जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि अर्जुन सिंह केवल अपनी मनमानी के लिए करोड़ों भारतवासियों की अनदेखी नहीं कर सकते।

सहारनपुर

रामपुर मनिहारन में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम इस सत्र से यौन शिक्षा शामिल करने के निर्णय के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने दिल्ली–सहारनपुर राजमार्ग पर सांकेतिक जाम लगाकर केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। देवबंद में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल किए जाने के फैसले से उलेमा और मुस्लिम बुद्धिजीवियों में रोश है। उनका कहना है कि इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा और गुरु–शिष्य रिश्ते की गरिमा खत्म हो जाएगी। जेवी जैन कॉलेज में छात्र कल्याण परिषद् की बैठक में माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले यौन शिक्षा पाठ्यक्रम की घोर निंदा की। इसे भारतीय संस्कृति पर सीधा हमला करार दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के जिला संयोजक सोहन मुखिया के नेतृत्व में दिल्ली–सहारनपुर राजमार्ग पर सांकेतिक जाम लगाकर विरोध दर्ज करवाया।

इन्दौर

"यौन शिक्षा या योग शिक्षा" विषय पर व्याख्यान

शिक्षा बचाओ आन्दोलन समिति, इन्दौर महानगर द्वारा दिनांक 8 सितम्बर 2007 को प्रबुद्धजनों तथा युवा छात्र–छात्राओं हेतु यौन शिक्षा या योग शिक्षा विषय पर एक गरिमापूर्ण तथा विचारोत्तेजक व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता

प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक एवं एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली के पूर्व सलाहकार श्री अतुल रावत। विषय प्रवर्तक थे प्रसिद्ध चिकित्सक एवं लेखक डॉ0 मनोहर भंडारी।

कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलन एवं देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। अतिथियों का स्वागत डॉ. वी. पी. सिंह, श्री लक्ष्मीनारण पटेल तथा श्री जयेश देसाई ने किया। श्री गोपाल माहेश्वरी ने हम चरित्र निर्माण न भूलें एकल गीत प्रस्तुत किया। शिक्षा बचाओ आन्दोलन समिति, इन्दौर के संयोजक डॉ. सुव्रतो गुहा ने शिक्षा बचाओ आन्दोलन की पृष्ठभूमि तथा गतिविधियों की जानकारी देते हुए यौन शिक्षा के माध्यम से भारत की सनातन योग की संस्कृति को पश्चिमी भोग की संस्कृति द्वारा प्रतिस्थापित करने के कुत्सित प्रयास के विरुद्ध शिक्षा बचाओ आन्दोलन के राष्ट्रव्यापी अभियान की दशा एवं शिक्षा का विश्लेषण किया।

विषय प्रवर्तक डॉ. मनोहर भंडारी ने अपने सारगर्भित उद्‌बोधन में इस तथ्य को रेखांकित किया कि योग शिक्षा एवं यौन शिक्षा में परस्पर सामजस्य असंभव है। योग शिक्षा के माध्यम से निरोगी काया, एकाग्रचित मन तथा आत्मीय आनंद प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यौन शिक्षा द्वारा यौन कुंठा, हताशा एवं कुत्सित मनोवृत्ति ही जन्म लेती है। उन्होंने अमेरिका तथा यूरोप के देशों के आंकडों के माध्यम से बताया कि यौन शिक्षा के फलस्वरूप उन देशों के अविवाहित युवतियों के गर्भधारण एवं गर्भपात यौन विकृतियों आदि के क्षेत्रों में भयावह परिदृश्य निर्मित हुई है जिसे भारत में दोहराने की अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती।

मुख्य वक्ता श्री अतुल रावत ने अपने ओजस्वी उद्‌बोधन में इस शाश्वत तथ्य को प्रतिपादित किया कि सनातन योग शिक्षा की परम्परा वाले भारतवर्ष में पश्चिम से आयातित यौन शिक्षा का कोई स्थान नहीं हो सकता। योग शिक्षा बनाम यौन शिक्षा वास्तव में पूर्वी तथा पश्चिमी सभ्यताओं के टकराव को प्रतिबिम्बित करती है।

कार्यक्रम का समपान वन्दे मातरम् गीत से हुआ। कार्यक्रम में प्रसिद्ध पत्रकार श्री कृष्ण कुमार अष्ठाना, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री राधेश्याम शर्मा सहित अनेक गण्यमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री विकास दवे ने तथा आभार प्रदर्शन श्री अरविन्द बंडी ने किया।

Shiksha Bachao demonstration before Delhi Assembly against sex education

Thousands of activists of Shiksha Bachao Andolan Samiti staged a massive demonstration at Delhi Assembly on September 18 to protest against the Delhi Government's move to introduce sex education in schools. The protestors demanded the government to stop it forthwith as has been done in some other states. Addressing the demonstrators, Shri Dina Nath Batra, Convener Shiksha Bachao Andolan Samiti, said the Delhi Government has introduced sex education in Delhi in the name of Adolescence Education and it aims to teach graphically the use of condoms to the students between the ages of 12-18 years, which would only encourage them to experiment with sex at an early age. He said the teaching material is full of explicit images of naked boys and girls in different stages of growth and the class activities shown in the book require students to touch each others' body parts including private parts. He pointed out that because of such objectionable features, ten states have already banned this syllabus, which has prepared and promoted by UNICEF, UNFPA and WHO. He also pointed that it is against the law to impart sex education to children between the ages of 4-18 years.

Addressing the demonstrators, Dr Harsh Vardhan, Delhi BJP president, who also raised the issue of sex education in Delhi Assembly on September 14 under rule 280, said the syllabus prepared for sex education would further increase the crimes and it crosses all limits of morality. He appealed to Delhi Chief Minister Smt. Sheila Dikshit to stop it forthwith.

Shri Atul Kothari, co-convener of Shiksha Bachao Andolan Samiti, said the NCERT has already declared that this would create a problem not only for the country but also for the whole world. Shri R.C. Jain, president of Delhi Public School Association, described it the childish act of the government. He said it would spoil the young generation. Shri Sahib Singh Chauhan, MLA, said they would not allow the government to spoil the young generation and would oppose it till their last breath. ■

Report

National Seminar on

"National Knowledge Commission's Recommendation on Higher Education"

19th - 20th September 2007,Bangalore

The National Seminar on "National Knowledge Commission's Recommendation on Higher Education" was organized jointly by the Department of Higher Education, Government of Karnataka, Bangalore University and Centre for Educational and Social Studies, Bangalore on 19th - 20th September 2007 in Central College Campus, Bangalore.

The National Seminar was inaugurated on 19th September 2007 by Shri D.H. Shankaramurthy, Honourable Minister for Higher Education, Karnataka. In his inaugural speech Shri D. H. Shankaramurthy stressed the need for critical assessment of present system of higher education in the country. Prof. P. Balaram, Director, Indian Institute of Science and Member of the National Knowledge Commission presented the scope and perspective of National Knowledge Commission and the future action proposed by the Commission in this regard. In his presidential address his excellency the Governor of Karnataka Sri Rameshwar Thakur examined the need for developing a concern for quality in higher education. He emphasized the responsibility of higher education in building a prosperous and peaceful Indian for the 21st century.

Professor H.A. Ranganath, Vice Chancellor, Bangalore University welcomed the gathering and explained the objectives of the seminar. Professor Vignette N. Bhat, Director, Centre for Educational and Social Studies, Bangalore, Proposed the vote of thanks.

On 19th September 2007, a video conference with Shri Sam Pitroda, Chairman, National

Knowledge Commission was arranged. During the course of over 45 minutes, Mr. Pitroda spoke on the objectives of National Knowledge Commission and its functioning in detail. In addition, he answered several questions asked by the seminar participants. Highlight of the video conference was Mr. Sam Pitroda's dialogue with the Minister for Higher Education, Karnataka.

The Valedictory function of the National Seminar was held on 20th September 2007. Prof. S.L. Rao, Chairman, ISEC Bangalore, in his valedictory address discussed various issues related to improving higher education system in India. Chief Guest of the function Professor B.K. Chandrashekhar, Honourable Chairman, Karnataka Legislative Council, highlighted the role of government and society in making higher education more relevant. In his presidential address, Shri D.H.Shankarmurthy, Minister for Higher Education, Government of Karnataka, explained various measures taken by the Government to extended higher education to increasing number of needy people in the State. Prof. P.V.Krishna Bhat, educationist and Syndicate member, Kuvempu University has expressed concern over and the need for improving higher Education in the country. Prof. P.V.Krishna Bhat educationist has expressed concerned towards improving higher Education. Dr. Vighnesh N. Bhat, Director, Centre for Educational and Social Studies, Bangalore proposed the vote of thanks. ■

कांग्रेसी और वामपंथी सरकारों ने सदैव आस्था से खिलवाड़ किया है : सुरेश भट्ट

रामसेतु के मुद्दे पर 13 सितं. को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में अभाविप ने अपना मत स्पष्ट किया। जिसमें कहा गया कि केन्द्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में भगवान श्रीराम के अस्तित्व को ही नकारना इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं व भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अभाविप ने केन्द्र सरकार की इस कार्यवाही की कड़ी निंदा एवं भर्त्सना की है। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेश भट्ट ने कहा कि सरकार रामसेतु को तोड़ने के लिए बहुसंख्यक समाज की आस्था को चोट पहुंचाने का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि "इतिहास गवाह है कि जब भी केन्द्र में कांग्रेस व वामपंथी सरकार में आये हैं, तब तब उन्होंने हमेशा इस देश की महान संस्कृति, परंपरा एवं बहुसंख्यक समाज की आस्था के प्रतीक चिन्हों, स्थलों व महापुरुषों को अपना निशाना बनाते हुए उनका अपमान किया है। वामपंथी कभी भी इस दश की गौरवमयी संस्कृति की प्राचीनता व देश का सम्मान व स्वाभिमान बढ़ाने वाली किसी बात का समर्थन नहीं कर सकते हैं।" केन्द्र की सरकार ने वामपंथियों के दबाव में आकर ही सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का हलफनामा दायर किया है। साथ ही दश की जनता से आह्वान किया गया कि वह केन्द्र सरकार कि इस दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देते हुए यूपीए सरकार को उखाड़ फेंके, जिससे उसे सबक सिखाया जा सके।

छात्रसंघ चुनावों पर रोक लोकतंत्र विरोधी

उत्तर प्रदेश में छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगाए जाने के प्रदश सरकार का फैसला लोकतंत्र विरोधी, छात्र विरोधी एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना है। यह बात अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट ने लखनऊ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः इनके प्रशिक्षण के लिए शिक्षा परिसरों में छात्रसंघों का गठन एक प्रभावी माध्यम है। छात्र कल का नहीं अपितु आज का नागरिक है, उसकी दश में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका बनती है। ■

मुलाकात

गीता ताई गुंडे
(पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, अभाविप)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्षा *सुश्री गीता ताई गुंडे* से विभिन्न मुद्दों पर *"उमाशंकर मिश्र"* द्वारा की गई बातचीत के प्रमुख अंश –

छात्रसंघ चुनाव चाहे वो जेएनयू के रहे हों या फिर डूसू के, पिछले काफी समय से विद्यार्थी परिषद् को असफलता ही हाथ लग रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं?

विद्यार्थी परिषद् के अपने कुछ सिद्धांत हैं, चुनाव जीतने के लिए हम उनकी अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि विद्यार्थी परिषद् के लिए चुनाव एकमात्र कार्यक्रम नहीं है। बल्कि छात्रों के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में से मात्र एक कार्यक्रम है। इसलिए अन्य छात्र संगठनों की तरह विद्यार्थी परिषद् राजनीतिज्ञों को आश्रय न लेकर मुद्दों की बात करता है। जबकि लम्बे समय से देखा जा रहा है कि परिषद् के मुख्य प्रतिद्वंद्वियों द्वारा न केवल धन एवं बल का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इन सब के बावजूद जमीनी स्तर पर आज भी छात्र एवं छात्राओं का समर्थन विद्यार्थी परिषद् के साथ ही है। बात चाहे हाल ही में सम्पन्न हुए भोपाल छात्रसंघ चुनाव की रही हो, इंदौर छात्रसंघ की अथवा हिमाचल छात्रसंघ चुनाव की महाविद्यालीय स्तर पर छात्रों का हुजूम परिषद् के साथ रहा है।

उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान जैसे राज्यों में छात्रसंघ चुनावों पर प्रतिबंध लगाए जाने को परिषद् किस नज़रिये से देखता है?

इस तरह से छात्रसंघ चुनावों पर प्रतिबंध लगाए जाने के कदम को सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम इस देश के नागरिक और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। युवाओं को ऐसे में इस प्रक्रिया से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अभाविप मानती है कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है। ऐसे में वर्तमान परिवेश और उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए इस तरह की गतिविधियों को नकारा नहीं जा सकता। यह कहा जाना कि इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है, एक बेबुनियाद तथ्य है। विद्यार्थी परिषद् के इतिहास को पलट कर देखें तो इसके छात्र नेता आज प्रतिष्ठित स्थानों पर हैं। लेकिन यदि लोग राजनीति की पाठशाला मानकर सिर्फ चुनाव लड़ने के मकसद से शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने लगें तो ऐसे में शिक्षा का स्तर ही नहीं छात्रों के बुनियादी मुद्दे भी गर्त में चले जाते हैं। लिंगदोह समिति की भी सिफारिश है कि छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए और विद्यार्थी परिषद् का भी प्रयास है कि इसे अमल में लाया जा सके।

भारत की सांस्कृतिक विरासत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार ही करोड़ों लोगों की आस्था को दरकिनार कर रामसेतु जैसी ऐतिहासिक विरासत को ही धवस्त करने पर तुली है। इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं। क्या सरकार पर कोई बाहरी दबाव है?

रामसेतु के मुद्दे पर सरकार का रवैया बड़ा ही गोलमोल सा रहा है और अभी तक उसका मत स्पश्ट नहीं हो सका है। सरकार द्वारा पहले एफिडेविट फाईल करना और फिर वापस ले लाना इस बात के ही संकेत देता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। इस बात की भी संभावना इंकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान केन्द्र सरकार अपनी अमेरिका–परस्ती के चलते अपने ही देश के लोगों की आस्था से खेल रही है। इस तरह के प्रतीक हमारी विरासत हैं और इनसे करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी

है। सरकार का कर्तव्य है ऐसे प्रतीकों का संरक्षण करना, लेकिन विडंबना ही है कि सरकार ठीक इसके विपरीत कर रही है। लोगों की श्रद्धाभावना को इस तरह के कृत्यों से ठेस पहुंचाकर आखिर सरकार क्या अर्जित करना चाहती है। बात यदि विकास की है तो इसके लिए सेतु को तोड़ने की बजाय अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। आज रामसेतु को तोड़ने की बात की जा रही है। अगर कोई कह दे कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है तो क्या सरकार मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थानों को तोड़ना शुरु कर देगी।

वर्तमान युवा पीढ़ी के समक्ष शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी किस तरह की चुनौतियां हैं?

रोजगारपरक शिक्षा समय की आवश्यकता बन चुकी है। आधुनिक परिवेश में अल्पशिक्षित व्यक्ति में भी उद्यमीय कौशल का विकास करने के प्रयास करने होंगे। ऐसे में बुनियादी शिक्षा के स्वरूप में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी चाहिए। इसके अलावा किसी एक शैक्षिक धारा को ही लेकर चलना भी उचित नहीं है। अर्थात् अगर आईटी का चलन है तो अन्य विषयों को हाशिये पर धकेल दिया जाना उचित नहीं कहा जा सकता। सभी विषयों को समान स्तर पर ही लेना चाहिए। लोगों को रोजगारपरक शिक्षा मिले इसके लिए स्थानीय स्तर पर संसाधनों की बेहतर व्यवस्था की जरूरत होगी। इस पूरे कार्य अंजाम देने के लिए एक दीर्घकालीन नीति की भी आवश्यकता होगी।

बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को लेकर विद्यार्थी परिषद् ने जोर–शोर से देश भर में अभियान चलाया है, लेकिन चीन ने हमारे देश के एक बड़े भू–भाग पर कब्जा किया हुआ है और निरंतर वह आगे ही बढ़ता जा रहा है। इस बारे में क्या परिषद् ने सोचा है?

परिषद् राष्ट्रीय हित से जुड़े सभी विषयों पर कार्य करती रही है, करती है और करती रहेगी। हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश से खदेड़ने का अभियान छेड़ा और हमारे कार्यकर्ताओं की टीम भी भारत–बांग्लादेश सीमा का सर्वेक्षण करने भी जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि परिषद् चीन की कारगुजारियों से अनभिज्ञ है। हमने समय समय केन्द्र सरकार को इस तरह के विषयों से चेताया है। लेकिन यह बहुत बड़ी त्रासदी है कि हमारी सरकार रामसेतु को ढहाकर लोगों की आस्था को धूल धुसरित तो कर सकती है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा जैसे बुनियादी विषय केन्द्र सरकार की प्राथमिकता से किस कद्र बाहर हैं, यह इसी बात का प्रमाण माना जा सकता है। सरकार का यह रवैया बिल्कुल गलत है। ऐसे में हमारी कमजोरियों का फायदा तो अन्य देश उठाते ही रहेंगे। इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

हमारे देश में महिलाओं को दर्जा हमेशा दोयम बना रहा है, ऐसे में छात्राओं को मुख्यधारा में लाने के लिए परिषद् किस तरह की गतिविधियों का आयोजन करती है?

परिषद् हमेशा से ही विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर उनमें व्यक्तित्व के अपेक्षित गुणों के विकास हेतु विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन करती रही है। छात्राओं का दूसरी पंक्ति में होने के अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से छात्रों की अपेक्षा छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। अभाविप छात्राओं में आत्मविश्वास कूट–कूट कर भर देने के लिए कृतसंकल्प है, जिसके लिए समय समय पर सामाजिक विकास, छात्राओं के मानसिक विकास एवं पर्सनाल्टी डेव्लपमेंट के लिए विभिन्न स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सम्मेलनों एवं सेमीनारों में छात्राओं को मंच देकर विद्यार्थी परिषद् ने उनके उत्साह को हमेशा बढ़ाने का कार्य किया है। ■

Report

National Seminar on

" NAAC Accreditation Methodology: Assessment and Suggestions"

25th August 2007, Pune

Quality of Higher education is a matter of prime concern. An autonomous body called National Assessment and Accreditation Council (NAAC) was established by UGC in 1994 and since then NAAC is doing the work of assessment and accreditation of colleges and universities in India.

A National Seminar on " NAAC Accreditation Methodology: Assessment and Suggestions" was organised on 25th August 2007 at Pune.

Dr.Arun Nigavekar, founder Chairman of NAAC inaugurated the seminar. In his inaugural speech focused on quality in flexible higher education.National Vice President of ABVP Shri Milind Marathe talked about the five focus points of the seminar. He said that professional courses also be certified and their integrity is important. He mentioned the strong commitment for the quality education on part of assessors.

Shri Anirudha Deshpande, Member, Executive Council, NAAC, explained the new methodology of assessment and accreditation. The need for Institutional eligibility for quality Assessment, its status, the guidance provided by NAAC before and after IEQA was also discussed. He also mentioned that the new method is more transparent, reliable and objective.

Prof. Sadashivan, represented the teacher's organisation AIFUCTO, explained why it opposed the assessment and accreditation by NAAC. Their opposition was to the link between 'grade and aid'. He said that 99% people particularly running professional institutions looks towards education as a milking cow.

In the valedictory function the renowned economist and Vice Chancellor of Pune University, Dr.Narendra Jadhav said Accreditation must be mandatory. He said that today we are standing at cross roads. The three powerful engines of growth in world economy US, Japan and Europe are now slowing down and major part of growth in world economy is now governed by India and China. To become economic super power by 2020 as dreamed by Dr.Abdul Kalam, the greatest strength of India is her youth. In the view of globalisation of educational system, Dr. Jadav emphasised the linkage of our accreditation system with that in other developed countries .He proposed that five start universities like Pune University can also perform the task of accreditation in other states so that the huge task that is remaining can be accelerated. He also mentioned the need for making a new education policy because we do not have the one since 1993. He congratulated ABVP for organising this seminar which, he said will help in crystallising our ideas and thoughts on path-making things.

The seminar was attended by 55 participants and 8 speakers from 15 states. Principals, Directors of educational institutions, NAAC coordinators of colleges and State ans National Level activists of ABVP were among the participants.

Dr.M R Kurup,Secretary, Kelkar Education Trust, Mr. Arunkumar Khannur, Chairman and CEO,ISQT processing and consulting services Pvt Ltd, Shri Suresh Bhatt, National General Secretary, ABVP, Shri Atul Kothari,National Joint Org. Secretary, ABVP, Shri P V Krishna Bhat were also presented their views in the seminar. ■

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्राओं का प्रांतीय सम्मेलन 30 सितम्बर को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर (कांतिकपूर) बरेली में संपन्न हुआ। जिससे पूरे प्रदेश के 16 स्थानों से 534 छात्राओं ने भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सुश्री गीता ताई गुंडे उपस्थित रही । सम्मेलन में एक वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य पर एक प्रस्ताव भी पारित हुआ।

सम्मेलन में छात्राओं को सम्बोधित करते हुए अ.भा.वि.प. की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सुश्री गीता ताई ने कहा कि आज भोगवादी समाज में महिलाओं को भोग की वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। इस स्थिति से महिलाएं तभी उभर सकती है। जब वे झांसी की रानी से प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह बनें। उन्होने छात्राओं को वीरागना रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर अपने जीवन मे कुछ कर गुजरने की बात कही। उन्होने वर्तमान शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि आज बहुत तेजी से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है।

सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तरांचल प्रदेश की प्रदेश मंत्री भावना वोरा ने कहा कि आज की महिलाएं भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह दोनों हाथों में अपनी योग्यता रूपी तलवार लेकर जीवन के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका का उचित निर्वाहन कर हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा सिर्फ विद्यार्थी परिषद ही छात्र–छात्राओं को रचनात्मक प्रतिनिधित्वात्मक व आन्दोलनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र के पुन निर्माण की दिशा में प्रेरित करती है।सम्मेलन की अध्यक्षता –खंडेलवाल कॉलेज की एक्ज्यूकिटिव डायरेक्टर श्रदा खंडेलवाल जी ने किया।

हरियाणा में छात्रा सम्मेलन सम्पन्न

हरियाणा में छात्राओं के समक्ष चुनौतियों को लेकर हाल ही में अभाविप द्वारा प्रांत स्तर पर एक विशाल छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के प्रति बरते जाने वाले भेदभाव, लैंगिक असमानता, कन्या भ्रूण हत्या और यौनाचार जैसे गंभीर विषयों पर चिन्ता व्यक्त की गई। सम्मेलन में यह अनुभव किया गया कि आर्थिक दृष्टि से प्रदेश के समृद्ध होने के बावजूद यहां महिलाओं की स्थिति में संतोषजनक सुधार सुधार नहीं हो सका है। प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या 865 है, जो महिलाओं के प्रति अपनाए जाने वाले उपेक्षित रवैये की बात को पुख्ता करता है। सम्मेलन में हरियाणा की वर्तमान परिस्थिति तथा छात्रा समस्याओं पर प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी ने अभाविप की कार्यपद्धति की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी विचार वाले संगठन के साथ जुड़कर ही छात्राएं इस तरह की चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। भ्रूण हत्या केवल भाषण या संकल्प का विषय नहीं है। इस समस्या का समाधान मातृशक्ति स्वयं समाज का नेतृत्व करके ही कर सकती है, छात्राओं को समाज का नेतृत्व करने का संकल्प करना चाहिए। स्थानीय वैश्य महिला महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता, अभाविप राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती पायल सिरोही ने कहा कि आज की नारी को स्वयं अपने अधिकारों का निर्धारण कर उन्हें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। राष्ट्रिय उपाध्यक्षा ने भ्रूण हत्या को सामाजिक कलंक बताते हुए इसे समाप्त करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि बाबा मस्तनाथ चिकित्सा महाविद्यालय की महिला रोग विशेषज्ञ डा0 अंजू आहूजा ने कहा कि आज देश में जनसंख्या वृद्धि तथा भ्रूण हत्या ही ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं, जो भारतीय समाज को पतन की तरफ ले जा रही हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता इण्डस स्कूल की निदेशक श्रीमती एकता सिन्धू ने की और कहा कि अभाविप समाज निर्माण का सशक्त मंच है, जो सही अर्थों में राष्ट्र पुनिर्माण का कार्य कर रहा है।

भोपाल छात्रसंघ चुनावों में अभाविप की धाक

अगस्त माह के दूसरे पखवाड़े में सम्पन्न हुए भोपाल छात्रसंघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। भोपाल में 32 कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव हुए थे, जिसमें से 25 में 11 कॉलेजों में अभाविप ने विजय हासिल की। वहीं एनएसयूआई भेल कॉलेज के अलावा कहीं भी जीत नहीं हासिल कर सका। इसके अलावा बीएसएफ और राकांपा के भी सदस्य कुछेक समितियों में चुने गए।

इंदौर में भी लहराया परिषद् का परचम

अगस्त माह के दूसरे पखवाड़े में सम्पन्न हुए इंदौर छात्रसंघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद् ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभाविप ने अपने दावे के मुताबिक शहर के 30 में से 20 कॉलेजों में जीत हासिल की है। मुख्य मुकाबला यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और एनएसयूआई के बीच था।

भोपाल में अभाविप के प्रांतीय कार्यालय निर्माण का शुभारंभ

देश की बदहाली दूर करने और उसे ताकतवर बनाने का श्रेय किसी पार्टी को नहीं बल्कि नौजवानों और टैक्नोक्रेट को जाता है, जो शिक्षा एवं तकनीक के क्षेत्र में अपनी मेहनत से

विदेशो मे सफलता के झंडे गाड रहे हैं। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर कार्यवाह मा.सुरेश सोनी ने 19 अगस्त को भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रांत कार्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर कही। इस मौके पर परिषद् के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने कहा कि वर्ष 1949 से परिषद् ने युवाओं के लिए संस्कार केन्द्र और विकास केन्द्र स्थापित किये हैं। समारोह में परिषद् के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विष्णुदत्त शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

विजय भारत विषय पर तकनीकी– प्रोद्योगिक कांफ्रेंस आयोजित

गाजियाबाद :15–16 सितम्बर को राजकुमार गोयल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में 2 दिवसीय 'तकनीक–प्रोद्योगिक कांफ्रेस' का आयोजन 'विजय भारत' विषय पर किया गया, जिसमें तकनीकी एवं प्रबन्धन के स्नातक, परास्नातक के लगभग 115 छात्र/प्राध्यापक सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के विभिन्न क्षेत्रों से सम्मिलित हुए।

एमबीए, बीबीए, बीटेक, एमबीबीएस, बी फार्मा, एमसीए, बीसीए आदि विभिन्न तकनीकी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हस्तिओं की सहभागिता से जुड़े बुद्धिजीवियों की सहभागिता से चलने वाली इस काफ्रेंस के 'उद्घाटन सत्र' में प्रसिद्ध 'अर्थशास्त्री एवं आईआईएम के पूर्व प्रोफेसर श्री भरत झुनझुनवाला' मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहें। भारत विजन का दृष्टिकोण रखते हुए श्री झुनझुनवाला ने कहा कि भारत शीघ्र ही विकसित राष्ट्र के रूप में पहचाना जाएगा। इस हेतु समस्त संभावनाएं विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा सर्वे भवन्तु सुखनः की स्वीकार्यता के चलते ही यह संभव होगा। 'परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेश भट्ट जी' ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए तकनीकी क्षेत्र में भारत की विश्व को देन विषय पर गौरवपूर्ण व्याख्यान दिया।

सायंकालीन सत्र में तकनीकी छात्रों को विजन–2020 में भूमिका विषय पर प्रतिभागियों ने भारत को सन् 2020 तक विश्व का सिरमौर बनाने के लिए अत्यन्त रचनात्मक व आत्मविश्वास से लवरेज विचार प्रस्तुत किए। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरिओम जी ने सारगर्भित तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए। इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री अतुल कोठारी जी ने भारत के तकनीकी क्षेत्र में उदय पक्ष को विभिन्न उदाहरणों द्वारा रखते हुए उपस्थित छात्र शक्ति का मार्गदर्शन किया।

तृतीय सत्र में सामाजिक क्षेत्र में कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य कर रहे दिव्य सेवा मिशन, के आशीष गौतम जी, एवं अंधता निवारण के लिए कार्य कर रहे वरदान नेत्र चिकित्सालय गाजियाबाद के श्री कमलेश जी ने उनके मिशन द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। दूसरे दिन भी कार्यक्रम के तीन सत्र हुए। प्रथम सत्र 'प्रबंधन और गीता' था, जिसपर सुश्री सुविज्ञा जी त्रिपाठी बोलीं। इस सत्र की अध्यक्षता इंटिग्रेटिड एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टैक्नालॉजी गाजियाबाद के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर श्री पंकज गुप्ता ने की। दूसरा सत्र 'उद्योग जगत की अपेक्षाएं' विषय पर पैनल चर्चा का था। इसमें स्लीपवेल कंपनी की अध्यक्ष श्री शीला गौतम एवं स्टील इंडस्ट्री के विश्वेन्द्र गोयल जी का सान्निध्य छात्रों को मिला। अंतिम सत्र के पश्चात प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव परिषद के प्रान्त संगठन मंत्री श्री धर्मपाल जी ने प्रस्तुत किया। उद्घाटन समारोप सत्र की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी की। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री श्री नीतेश तोमर, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री दिनेश जी, प्रान्त प्रचारक श्री दिनेश कुमार, गाजियाबाद महापौर दमयन्ती गोयल, पूर्व सांसद डा. रमेश चन्द्र तोमर, डा. राजकुमार गोयल इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीयनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी के निदेशक डा. के.वी. नायक मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संयोजक के नाते जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट के विभागाध्यक्ष प्रो. राजीव सिजरिया ने किया।

Karnataka

Ratha Yatra Conducted to Mark 150th Year of First War of Independence.

To mark the 150th year of the First War of Independence and birth centenary of freedom fighter Bhagat Singh, the Akhil Bhatratiya Vidyarthi Parishad has launched a month-long State-wide Ratha Yatra to spread the message of patriotism among the youth.

The Ratha Yatra was flagged off at the premises of Sadvidya Educational Institution by Star of Mysore Editor K. B. Ganapathy.

Speaking on the occasion ABVP Organising Secretary N. Ravikumar said that the Rath Yatra would travel in all the districts of the State spreading the message of patriotism and martyrs who had laid down their lives for the nation. The entire student community back the legendary Bhagat Singh, he observed.Zonal Boudhik Pramukh

V. Nagaraj observed that the Indian culture was put down during the British rule till valiant fighters like Jhansi Rani Lakshmi Bai, Bhagat Singh, Mangal Pandey and others confronted the British. Over 3 Lakh people laid down their lives during the freedom struggle. The Yatra would revive the historical events, he said.

Advocate O. Shyam Bhat, GRS Fantasy Park Partner Yogesh Dange, Sadvidya Institutions Secretary Prof K.V. Arkanath and Principal Satyan participated. ABVP City president N.R. Manjunath welcomed. Over 500 students were present. The Rath carried portraits of several freedom fighters.

Delhi

ABVP demands action against NSUI panel

Accusing the administration of acting at the behest of Congress party during the recent Delhi University Students' Union (DUSU) elections, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) said the authorities must act against the National Students' Union of India (NSUI) whose candidates openly flouted the model code of conduct for the polls.

In this regard an ABVP delegation met Vice-Chancellor Deepak Pental and Chief Election Officer for the polls, Gurmeet Singh. If no action was taken within seven days, the organisation would "expose" the triumphant NSUI panel and call for a University bandh, said ABVP leaders in a press meet on September 10 in New Delhi.

"We told them that NSUI had openly flouted the model code of conduct by spending more than Rs.10,000, pasting posters all across the capital and distributing gifts like diaries. The authorities must take a strong action against all the violators, even if it includes the ABVP candidates. The attendance of two winning candidates of the NSUI panel did not meet the required percentage, but they got their attendance completed by their respective college principals. The Vice-Chancellor has assured us that a committee will be set up to look into all such issues," said Shri Sunil Bansal, ABVP Zonal Organising Secretary.

Alleging that Prof. Gurmeet Singh's role during the election process was "dubious", ABVP Delhi state secretary Niharika Sharma said: "He has been acting as a Congress worker. When a private television news channel aired a sting operation on Devraj Tehlan (DUSU Vice-President), the same evening we submitted a written complaint to the Chief Election Officer. Prof. Singh did not take any action against him and instead asked us to furnish proof. Who are we to provide proof? Should the University authorities not procure the tapes of that programme and act on it? They have made a mockery of the whole election process. The whole procedure has been very unfair this time."

Meanwhile, the ABVP claimed that despite such "difficult circumstances", there was an increase in its vote share in different colleges in 2007-08. "Our organisation got 23 per cent of total votes last year and this year it has shot up to 28 per cent. In 2006-07, we had won 60 posts at 23 colleges, while this year we have emerged victorious in 82 posts at 32 colleges," she said.

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad

ABVP

53rd National Conference

December 1 - 4,2007

Kanpur

Three years of Shiksha Bachao Andolan, Many battles won

- Atul Kothari -

Begining on July 2, 2004 the Shiksha Bachao Andolan, with the active support of the society, has successfully exhorted people to think about the history being taught to their children in schools and reject the distortion by vested historians outright. Apart from grilling the government in the court, a debate has also begun all over the country about the content of the textbooks. The overall three years efforts of the Shiksha Bachao Andolan Samiti has produced overwhelming results," said Shri Atul Kothari, co-convener of Shiksha Bachao Andolan Samiti.

He pointed out that with the formation of a national committee in Delhi, 29 other committees were formed at the State level involving over 450 workers of various organisations. "We are basically conducting three kinds of activities-awareness, agitation and legal battle. On the front of awareness campaign, a total of 41 booklets were published. Five booklets were published with the help of other organisations. These booklets are being sent to over 5,500 intellectuals. Lakhs of pamphlets were also distributed, more than 500 symposiums were held in which more than one lakh people participated," he said.

About the agitation, he said two big agitational programmes were held at the central level including dharna, demonstrations, meetings, etc. At both the times people from 15 to 22 Prants participated. In some Prants agitations were held even at the district and Sambhag level. Fifty other programmes of dharnas and demonstrations were held against the distortions in history textbooks of Indira Gandhi National Open University (IGNOU). Sixty-five workers had been put behind the bars for two to nine days for shouting slogans at the meeting of Central Education Council in Vigyan Bhavan.

About the legal battle Shri Kothari said a case was filed in Jaipur high court in 2004, which stayed the attempt of NCERT to change the syllabus in middle of the session. The petition filed in Alwar court also forced the NCERT to remove the objectionable passages about Lord Mahavira and Jains from the textbooks. The cases in Chandigarh, Allahabad and Delhi high courts are still going on.The Samiti had filed objections against 75 passages of history books by NCERT. The court has directed the NCERT to remove 67 passages and the NCERT has now assured the court to remove the remaining eight passages also by April 2008. It was due to the massive agitation against the distortion in history books of IGNOU that the HRD Minister had to announce the removal of the objectionable passage in Parliament itself within three days, he said.

The Samiti has also launched a massive agitation against sex education.Under the signature campaign launched against it more than five lakh signatures have been collected. A book entitled Red Alert has also been distributed for awareness.So far the governments of Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh have refused to impart sex education in their respective states.

"By and large with the efforts of the Samiti the issue of distortion of history has been discussed in both the Houses of Parliament.

Most of the issues that the Samiti took up in these three years were resolved positively. But the agitation will not stop till all the issues are resolved," Shri Kothari added. ■

Ratha Yatra conducted at Mysore (Karnataka) to mark the 150th year of 1857 and birth centenary of Bhagat Singh

हरियाणा (रोहतक) में आयोजित प्रांत छात्रा सम्मेलन में बोलते हुये मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी

बरेली (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में आयोजित प्रांत छात्रा सम्मेलन में उपस्थित अतिथि एवं प्रतिनिधिगण

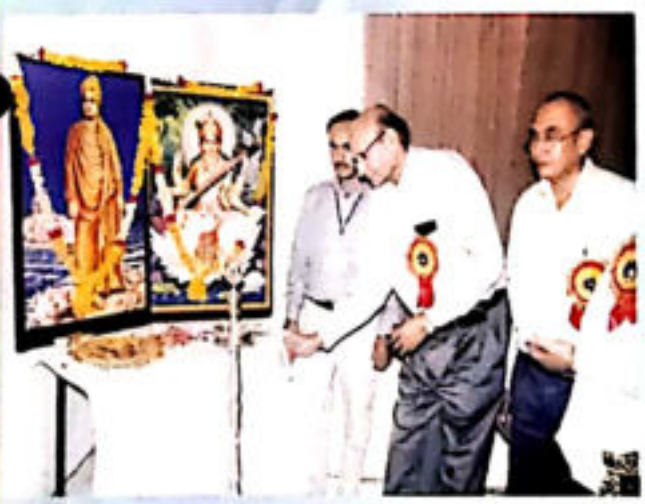

गजियाबाद में आयोजित 'तकनीक–प्रोद्योगिक कांफ्रेंस' का उद्घाटन करते प्रसिद्ध 'अर्थशास्त्री श्री भरत झुनझुनवाला

1857 की क्रांति की 150वीं वर्षगांठ पर मेरठ में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित

the torchbearer of nationalism.........

AKHIL BHARATIYA VIDYARTHI PARISHAD